विवाद समिति द्वारा नियुक्त बीकॉम पास सर्वेयर की योग्यता पर उठे सवाल

शिव शक्ति वेयर हाउस में गेहूं खरीदी पर विवाद

नवभारत/ नरसिंहपुर। जिले के शिव शक्ति वेयर हाउस में संचालित सहकारी समिति खमरिया के गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की परेशानी और अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गेहूं खरीदी के दौरान किसानों के लाट लगातार रिजेक्ट किए जाने, तुलाई में निर्धारित मात्रा से अधिक वजन लेने तथा कथित अवैध वसूली के आरोपों ने पूरे मामले को तूल दे दिया है। किसानों और किसान संगठनों ने इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले में सहकारी समिति खमरिया के समिति प्रबंधक दीपेंद्र राजपूत ने स्वीकार किया है कि खरीदी केंद्र पर अधिकृत सर्वेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण एक बीकॉम पास कर्मचारी मोहित मेहरा को सर्वेयर की जिम्मेदारी दी गई है। इस खुलासे के बाद किसानों में नाराजगी और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि जिस व्यक्ति को गेहूं खरीदी के तकनीकी मापदंडों की जानकारी ही नहीं है, वह किसानों के गेहूं को रिजेक्ट कर रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

खुद को नहीं पता पैरामीटर, किसानों के लॉट कर रहे रिजेक्ट

खरीदी केंद्र पहुंचे कई किसानों ने आरोप लगाया कि उनका गेहूं गुणवत्ता मानकों पर सही होने के बावजूद रिजेक्ट किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र में नमी, चमक और अन्य पैरामीटर के नाम पर बार-बार आपत्ति लगाई जा रही है। इससे किसानों को कई दिनों तक केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ किसानों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यदि व्यवस्था कर दी जाए तो वही गेहूं पास हो जाता है, लेकिन सामान्य किसान को परेशान किया जाता है। किसानों का आरोप है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

किसानों में बढ़ता आक्रोश

खरीदी केंद्र पर लगातार हो रही परेशानियों के कारण किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले मौसम की मार और उत्पादन लागत से वे परेशान रहते हैं, ऊपर से खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था उन्हें और संकट में डाल रही है। कई किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसान संगठनों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खरीदी केंद्रों की निगरानी बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है।

एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश

मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। एसडीएम संघमित्रा गौतम ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित छुस्ह्र को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने यह भी कहा कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शासन के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसानों और किसान संगठनों की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई हैं। यदि जांच में किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं तो खरीदी केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं किसान संगठन इस मामले को व्यापक स्तर पर उठाने की तैयारी में हैं। फिलहाल शिव शक्ति वेयर हाउस में गेहूं खरीदी को लेकर पैदा हुआ विवाद जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष कार्यवाही कर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

किसान संघ ने लगाए गंभीर आरोप

किसान संघ के जिला महामंत्री अभिषेक पटेल ने पूरे मामले को किसान विरोधी बताते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर लंबे समय से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं और शिव शक्ति वेयर हाउस का मामला उसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होता है। अभिषेक पटेल ने आरोप लगाया कि किसानों के गेहूं को जानबूझकर रिजेक्ट किया जा रहा है ताकि उनसे आर्थिक लेन-देन किया जा सके। उन्होंने कहा कि गरीब और छोटे किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। किसान कई किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं लेकर आते हैं, लेकिन केंद्र पर घंटों इंतजार के बाद उनका माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरीदी केंद्र में निर्धारित मात्रा से 300-400 ग्राम अधिक तुलाई की जा रही है। शासन द्वारा तय सीमा से अधिक वजन लेने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान संघ ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

बीकॉम पास कर्मचारी को बनाया सर्वेयर

समिति प्रबंधक दीपेंद्र राजपूत ने बताया कि खरीदी केंद्र में नियमित और प्रशिक्षित सर्वेयर उपलब्ध नहीं था। इसी कारण अस्थायी रूप से बीकॉम पास कर्मचारी मोहित मेहरा को सर्वेयर की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। हालांकि इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना तकनीकी प्रशिक्षण और अनुभव वाले व्यक्ति को खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी देना उचित है? गेहूं खरीदी में गुणवत्ता परीक्षण के लिए शासन द्वारा निर्धारित स्पष्ट मापदंड होते हैं, जिनके अनुसार ही खरीदी की जाती है। ऐसे में गैर-प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा किसानों के गेहूं का परीक्षण किए जाने पर पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता संदेह के घेरे में आ गई है।

तुलाई में गड़बड़ी के आरोप

किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र में प्रति बोरी 300-400 ग्राम अधिक वजन लेकर तुलाई में भी अनियमितताएं हो रही हैं। आरोप है कि निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं लिया जा रहा है, जिससे किसानों का अतिरिक्त अनाज बिना भुगतान के चला जाता है। किसानों ने मांग की है कि खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों और तुलाई प्रक्रिया की नियमित निगरानी होनी चाहिए। कुछ किसानों ने यह भी कहा कि यदि कोई किसान विरोध करता है तो उसके गेहूं में तुरंत कमी निकाल दी जाती है। इससे किसानों में भय और असंतोष का माहौल है।

पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल

पूरा मामला सामने आने के बाद सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली और खरीदी केंद्रों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति नहीं होगी और नियमों का पालन नहीं कराया जाएगा तो ऐसी समस्याएं लगातार सामने आती रहेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि समर्थन मूल्य खरीदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में तकनीकी कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। गुणवत्ता परीक्षण में छोटी सी गलती भी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में गैर-प्रशिक्षित कर्मचारियों से काम लेना प्रशासनिक लापरवाही माना जा सकता है।

इनका कहना है

शिव शक्ति वेयर हाउस में कई तरह की अनियमितताएं है, निर्धारित से ज्यादा वजन की तुलाई हो रही है इसके अलावा किसान के मॉल को पहले रिजेक्ट करते है फिर पैसे लेकर पास कर देते है, सर्वेयर की शैक्षणिक योग्यता सर्वेयर पद के अनुरूप नहीं है।

– **अभिषेक पटेल,** जिला महामंत्री, किसान संघ

कंपनी का सर्वेयर नहीं है और ना ही कंपनी सर्वेयर दे रही है, इसके अपने एक कर्मचारी को सर्वेयर बनाया है, सब मिलकर गेहूं देखते है, उसको नहीं पता पैरामीटर तो बाकी लोग भी है।

– **दीपेंद्र राजपूत,** समिति प्रबंधक

आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, मैने तुरंत छुस्ह्र को निर्देशित किया है, पूरी घटना की रिपोर्ट उनके द्वारा दी जाएगी, दोषी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

– **संघमित्रा गौतम,** एसडीएम गोटेगांव

कलेक्टर से शिकायत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

समय पर एंबुलेंस और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण महिला की मौत

नवभारत/ नरसिंहपुर। जिला अस्पताल में 108 एंबुलेंस कर्मियों की लापरवाही के कारण एक महिला मरीज की मौत हो गई थी। मृतका के बेटे ने हसन खान ने आज कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि समय पर एंबुलेंस और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मां की जान गई। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गोटेगांव निवासी हसन खान ने बताया कि उनकी मां छम्मो बी को हृदयाघात के बाद जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया था। आरोप है कि एंबुलेंस कर्मी वर्दी में नहीं थे और वाहन वार्ड से करीब 200 मीटर दूर खड़ा था। कर्मचारियों के न मिलने पर परिजन स्वयं मरीज को तेज धूप में व्हीलचेयर पर बैठाकर एंबुलेंस तक लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस में लिटाने के बाद कर्मचारी ने ऑक्सीजन पर्याप्त न होने की बात कही और जबलपुर जाने से मना कर दिया। अन्य कर्मचारियों ने भी परिजनों को हतोत्साहित किया। मजबूरी में परिजन मरीज को पीठ पर लादकर अस्पताल गेट तक लाए और ऑटो से निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका के बेटे ने शिकायत में बताया कि कर्मचारियों के नकारात्मक रवैये के कारण इलाज में देरी हुई। परिजनों के अनुसार, बाद में कर्मचारी अपने बचाव में ऑक्सीजन सिलेंडर भरा होने का दावा करने लगे। हसन खान ने कलेक्टर से मांग की है कि एंबुलेंस के लॉग बुक और कर्मचारियों की मौजूदगी की जांच कर उन्हें दंडित किया जाए।

अतरिया मार्ग पर झूलते बांस के झुंड दे रहे बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण

नवभारत/ गोटेगांव। गोटेगांव नगर से अतरिया कुंडा गांव की ओर जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग इन दिनों वाहन चालकों के लिए अत्यधिक खतरनाक साबित हो रहा है। इस मार्ग पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण जहां वाहन लगातार अनियंत्रित हो रहे हैं, वहीं सड़क किनारे लगे पेड़ों की लटकती डालियां भी हादसों का सबब बनी हुई हैं। विशेष रूप से अतरिया तिग्गा के पास मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर स्थित बांस के विशाल झुंड बीच सड़क तक लटक आए हैं। इनके नुकीले हिस्से सीधे मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को लग रहे हैं। इसी स्थान पर एक तीव्र अंधा मोड़ भी है, जिसके

कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे यहां कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस मार्ग से नियमित गुजरने वाले ग्रामीण और राहगीरों का कहना है कि संबंधित विभाग की इस घोर लापरवाही के कारण रोजाना लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।

एक नजर में

अतिक्रमण और चोरियों की भेंट चढ़ी बरगी कॉलोनी खंडहर में तब्दील हुई करोड़ों की सरकारी संपत्ति

नवभारत/ गोटेगांव। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) की बरहेटा अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) मुख्यालय कॉलोनी प्रशासनिक अनदेखी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो रही है। पिछले 20 वर्षों से देखरेख के अभाव और यहाँ किसी अधिकारी-कर्मचारी के न रहने से चोरों ने क्वार्टरों की खिड़कियां, दरवाजे, चौखट और सीमेंट शीट तक पार कर दी हैं। हद तो यह है कि चोरों ने सरकारी गोदाम का ताला तोड़कर वहां रखे कीमती लोहे के पाइप और अन्य जरूरी सामान भी गायब कर दिया है। सुविधाजनक और लावारिस माहौल पाकर बाहरी लोगों ने पूरी कॉलोनी परिसर पर अवैध कब्जा जमा लिया है। कुछ ग्रामीणों ने अपने पैतृक मकान बेचकर यहाँ बकायदा पक्के घर बना लिए हैं, तो वहीं गोदाम के पास झोपड़ियां डालकर मवेशी बांधे जा रहे हैं। मुख्य एसडीओ क्वार्टर पर एक शिक्षक का अवैध कब्जा है, जबकि विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके तीन चपरासी और सुपरवाइजर भी सालों से क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत का कहना है कि मुख्य नहर कार्यालय से रखरखाव का पत्र तो मिला था, लेकिन विभाग ने कॉलोनी को ग्राम पंचायत को विधिवत हस्तांतरित नहीं किया है, जिसके कारण बिना पूर्ण अधिकार के पंचायत कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी खुद यहाँ आकर व्यवस्था संभालें, संदिग्ध घरों की जांच कर चोरी का सरकारी सामान जब्त किया जाए और पूरी कॉलोनी को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

अधूरे निर्माण के साथ ठेकेदार ने छोड़ा पुल, सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मंडराया हादसे का खतरा

नवभारत/ गोटेगांव। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत उमरिया से बुढ़ैना गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर नदी के ऊपर नवनिर्मित पुल का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। पुल के मुख्य निर्माण के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हिस्सों में लोहे के एंगल तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अंतिम छोर के दोनों तरफ का एक बड़ा हिस्सा अब भी पूरी तरह खुला पड़ा है। इस स्थान पर काफी गहरी खाई जैसी स्थिति होने के बावजूद सुरक्षा दीवार या गाइड पिलर नहीं बनाए गए हैं, जबकि अमूमन ऐसे निर्माणों में पर्याप्त दूरी तक दोनों साइड पिलर खड़े किए जाते हैं। सुरक्षा मानकों की यह अनदेखी इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ साबित हो रही है। उद्घाटन से पहले ही काम समेटकर ठेकेदार के चले जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जिम्मेदार विभाग इस मामले का तत्काल संज्ञान ले और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल के शेष अधूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए।

हितग्राहियों को दिलाया जाएगा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ

नवभारत/ नरसिंहपुर। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नरसिंहपुर डॉ. प्रियंका राय ने बताया कि कलेक्टर रजनी सिंह की पहल पर पीएम जनमन एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले की जनजातीय बाहुल 91 ग्रामों एवं 91 आदि सेवा केन्द्रों में 18 मई 2026 से सबसे दूर सबसे पहले अभियान प्रारंभ किया जा चुका है। इस अभियान के तहत 25 मई 2026 तक इन ग्रामों में आदि सेवा केन्द्रों पर विशेष लाभ संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे और शासन की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को शतप्रतिशत लाभांवित किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता 25 मई तक सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 18 मई को जनजातीय कार्य विभाग की ओर से जनभागीदारी सप्ताह का शुभारंभ चिन्हित ग्रामों में किया जाएगा। अभियान के लिए चिन्हित सभी बसाहटों एवं आदि सेवा केन्द्र स्तर पर संतृप्ति शिविर एवं पौधरोपण का अभियान चलाया जाएगा।

व्यापारियों से अवैध वसूली और निर्माण कार्य में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग

नवभारत/ तेंदूखेड़ा। क्षेत्र में इन दिनों प्रशासनिक और विभागीय भ्रष्टाचार के मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं। हाल ही में अनुभाग स्तर के एक प्रमुख कार्यालय में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम द्वारा रीडर बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद यह चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई है कि कार्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी के शुरुआती कार्यकाल में ही इस स्तर का भ्रष्टाचार पनप रहा था तो आगे स्थिति और कितनी भयावह होती।

मंडी कर्मचारियों के माध्यम से व्यापारियों से वसूली का आरोप

ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बाद तेंदूखेड़ा कृषि उपज मंडी भी सुर्खियों में आ गई है। क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि जब से संबंधित अधिकारी को भारसाधक का प्रभार मिला था तभी से मंडी में घोष विक्रय की आड़ में

लाइसेंसधारी व्यापारियों को नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा था। जांच करने और लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर तेंदूखेड़ा मंडी सीमा मदनपुर राजमार्ग और डोभी तक का कोई भी व्यापारी शोषण से अछूता नहीं रहा। आरोप है कि मंडी में वर्षों से जमे कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलेआम अवैध राशि के लिफाफे पहुंचाए जा रहे थे। नाम न छापने की शर्त पर एक व्यापारी ने बताया पिछले दो तीन महीनों में व्यापारियों का जिस तरह से मानसिक और आर्थिक शोषण हुआ है । वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। आगामी सीजन में व्यापार प्रभावित होने के डर और मंडी प्रशासन की कार्रवाई के खौफ के कारण हम चुप रहने को मजबूर थे। क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने इस पूरे सांठगांठ की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

घटिया निर्माण दुकान शेड की गुणवत्ता पर उठे सवाल: मंडी परिसर में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुकान शेड का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि युवाओं से जिस अनुपात में राशि ली गई है। उस स्तर का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता की भारी अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में क्षेत्रीय विधायक ने भी मौके का मुआयना कर निर्माण कार्य की घटिया गुणवत्ता को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे। इसके बाद काम तो दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अब दुकानों पर लेंटर डलने से पहले ही घटिया निर्माण को छिपाने के लिए आनन फानन में प्लास्टर (छपाई) का काम शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर क्षेत्र के युवाओं और प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि दुकानों के आवंटन और निर्माण की गुणवत्ता की तत्काल जांच की जाए।

रखरखाव और पुट्टी के नाम पर लाखों का खेल: कृषि उपज मंडी में वित्तीय अनियमितताओं का एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि यह मंडी केवल सीजन के समय ही (हफ्ते-पंद्रह दिन) गुलजार रहती है लेकिन यहाँ से टैक्स के रूप में लाखों रुपये की आय प्रदर्शित की जाती है।?इस राशि का उपयोग किसानों के हित में करने के बजाय केवल कागजों और दिखावे के लिए शेड सुधार पेंचवर्क तथा रंगाई पुताई (पुट्टी) के नाम पर लाखों रुपये के टेंडर जारी कर दिए जाते हैं। क्षेत्र के किसानों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में मंडी से विभिन्न संदिग्ध कार्यों के भुगतान जारी किए जा रहे हैं। कृषकों ने पुरजोर मांग की है।

इनका कहना है

दुकान शेड निर्माण कार्य कर रहे संबंधित ठेकेदार को बोला गया है कि पहले लेंटर करवाओ बाद में छाप होगी।आऊटर और बीच में छाप शुरू कर दी गई थी जिसे बंद करवा दिया है।साथ ही पुट्टी पुताई वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है बरसात के कारण पुट्टी गिरने की बजह बताई जा रही थी। लेकिन फिर से टचिंग करने कहा गया है।जब तक काम सही तरीके से नहीं किया जायेगा ।

–**विकास मरकाम,** इंजीनियर कृषि उपज मंडी तेंदूखेड़ा

मेहरागांव की डिजिटल लाइब्रेरी बदल रही बच्चों का भविष्य

इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षा से ग्रामीण बच्चों को मिल रही नई उड़ान

नवभारत/साईखेड़ा। मेहरागांव। आधुनिक दौर में जहां डिजिटल शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तकनीकी शिक्षा की नई रोशनी पहुंचने लगी है। ग्राम पंचायत मेहरागांव में करीब नौ महीने पहले शुरू हुई डिजिटल लाइब्रेरी आज गांव के बच्चों और युवाओं के लिए ज्ञान, तकनीक और नई संभावनाओं का केंद्र बन गई है। इस डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षा, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक से जोड़ना था, ताकि गांव के बच्चे भी शहरों की तरह नई जानकारी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

बच्चों को मिल रहा डिजिटल ज्ञान: डिजिटल लाइब्रेरी में बीएसएनएल वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से बच्चे इंटरनेट पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन नई जानकारियां प्राप्त करने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और अन्य विषयों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। स्कूल खुलने के दौरान बच्चों को समय निकालने में कठिनाई होती थी, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में अब बड़ी संख्या में बच्चे लाइब्रेरी पहुंच रहे हैं। यहां वे अपना समय मोबाइल और रील देखने में बिताने के बजाय पढ़ाई और कंप्यूटर सीखने में लगा रहे हैं।

बेसिक से लेकर टैली तक सीख रहे बच्चे

लाइब्रेरी में बच्चों को बेसिक कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। बच्चे कंप्यूटर पर ड्रॉइंग बनाना, वर्ड फाइल तैयार करना, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग सीखना तथा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का उपयोग करना सीख रहे हैं। कई बच्चे पहली बार कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं और नई तकनीक के प्रति उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव के बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही यह सुविधा मिलने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। डिजिटल लाइब्रेरी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गांव की दो शिक्षित युवतियों रश्मि राजपूत और भूमिका को जिम्मेदारी दी गई है।

ग्राम पंचायत नोनी में साफ-सफाई का अभाव

नवभारत/ गोटेगांव। समीपवर्ती ग्राम पंचायत नोनी में साफ-सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के प्रमुख रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। निकासी ठप्प होने के कारण नालियां पूरी तरह जाम पड़ी हैं और उनका गंदा पानी अब सड़कों पर फैल रहा है। इस दूषित माहौल के कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस विकराल समस्या को लेकर सरपंच और पंचायत प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। अनेक बार शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी धरातल पर अब तक सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मांग की है कि पंचायत क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराई जाए ताकि लोगों को गंदगी से निजात मिल सके।

नाम सुधार सूचना

प्रियंका रजक निवासी पटेल वार्ड कन्देली नरसिंहपुर । 1. मैं स्व. गोविंदा मालवीया की विधवा एवं उनकी वैध Nok हूं। 2. यह कि मेरे पति 36 Assam Rifles में No.G/5022339H RFN (GD) के पद पर कार्यरत थे। 3. यह कि मेरे पति का सही एवं पूर्ण नाम Govinda Malviya (गोविन्दा मालवीय) है, किन्तु उनके Death Certificate में) Service Record में त्रुटिवश नाम केवल Govinda (गोविन्दा) अंकित हो गया है। 4. यह कि Govinda एवं Govinda Malviya दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं तथा दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। 5. यह कि मेरे पति के अन्य दस्तावेजो जैसे PAN CARD/ आधारकार्ड आदि में उनका नाम स्पष्ट रूप से Govinda Malviya अंकित है, अतः निवेदन है कि भविष्य में समस्त Service Record / Govt. Documents में मेरे पति का सही नाम Govinda Malviya ही दर्ज एवं मान्य किया जाए।